Regarding stray dog menace in Delhi

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): दिल्ली नगर निगम की स्थापना दिल्ली में मूलभूत सुविधाओं के लिए की गई है । इन्हीं मूलभूत सुविधाओं में एक सुविधा है कि जो बेघर जानवर है उनकी देखभाल करना और मनुष्य द्वारा किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हानि या प्रताड़ना जानवरों को न झेलनी पड़े और न जानवरों द्वारा भी मनुष्य को कोई कष्ट झेलना पड़े। इन सभी की देखरेख की जिम्मेदारी भी एमसीडी को दी गई थी। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी थी । दक्षिणी दिल्ली में बसंत कुंज के निकट बसी झुग्गी में रहने वाले एक ही परिवार के दो बच्चों को कुत्तों के हमले में दो दिन के अंतराल में अपनी जान गंवानी पड़ी। पूर्व में एमसीडी शासन में इस विषय पर गंभीर रूप से ध्यान दिया जा रहा था । परिणामस्वरुप, ऐसी घटना कभी हुई नहीं परंतु पिछले तीन महीने से नवगठित एमसीडी बनने के तुरंत बाद अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है । जबकि 3 महीने पूर्व नियमित रूप से कुत्ते का दस्ता द्वारा निरीक्षण कर ऐसे खतरनाक कुत्तों को पहचान कर उचित कार्रवाई की जाती थी परंतु दुर्भाग्यपूर्ण आज की स्थिति कुछ अलग है । पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में पुलिस ने एमसीडी को पत्र लिखकर मांग की है कि डॉग स्क्वायड द्वारा इस क्षेत्र में ऐसे खतरनाक कुत्तों को पहचान कर यहां से तुरंत उठाया जाए या उचित कार्यवाही की जाए ताकि यहां रहने वाले नागरिकों को आने वाले समय में कोई ऐसी परेशानी न झेलनी पड़े परंतु इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है । इसलिए कमिश्नर एमसीडी को निर्देश दिए जाएं कि हर जिला तहसील स्तर पर एक डॉग स्क्वायड बनाई जाए ताकि निरंतर निरीक्षण कर ऐसे सभी जानवरों को उठाया जाए या कोई अन्य उचित कार्रवाई की जाए । यह भी जानने को मिला है कि जानवरों का व्यवहार इसलिए ऐसा हो गया है क्योंकि जो आसपास वाले होटल है वो अपने बचे हुए मांसाहारी भोजन को कूड़े में डालकर जंगल में डाल देते हैं । दिल्ली प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी की जिम्मेदारी है कि ऐसे होटल को चिन्हित कर कार्रवाई की जाए

क्योंकि इसी कूड़े को यह बेघर कुत्ते खाकर अपना गुजारा करते हैं और कभी न मिलने पर उसके अभाव में आक्रामक हो जाते हैं और इस घटना को ना चाहते हुए भी अंजाम देते हैं क्योंकि दोनों विभाग एमडी व दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं इसलिए अनुरोध है कि दिल्ली सरकार को निर्देश दिए जाएं ताकि जल्द से जल्द इस पर उचित कार्रवाई हो सके।